



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1992/चैत्र 10, 1914

No. 220] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1992/CHAITRA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1992

का. प्रा. 250(अ)/18कक घाई. डी. प्रार. ए./92 - भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) के प्रादेश सं. 320(अ)/18कक/घाईडी प्रार. ए./79 तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रादेश कहा गया है) से संबंधित प्रोपेलो जिप्सर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्षों की अवधि

के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, बम्ब और और कृष्ण उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1992 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए इसे जारी रखने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। [द्वितीय भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय] (औद्योगिक विकास विभाग)] के आदेश

स का आ 246(अ)/18कक/आई डी आर ए /32, तारीख 15 मई, 1982

सं. का आ 822(अ)/18कक/आई डी आर ए /82, तारीख 24 नवम्बर 1982,

स का आ 385(अ)/18कक/आई डी आर ए /83, तारीख 31 मार्च, 1983,

सं. का. आ 872(अ)/18कक/आई डी आर ए /83, तारीख 30 नवम्बर, 1983,

स का आ 472(अ)/18कक/आई डी आर ए /84, तारीख 28 जून, 1984,

स का आ 976(अ)/18कक/आई डी आर ए /34, तारीख 29 दिसम्बर, 1984,

सं. का. आ 275(अ)/18कक/आई डी आर ए /85, तारीख 29 मार्च, 1985,

स का. आ 148(अ)/18कक/आई डी आर ए /86, तारीख 31 मार्च, 1986,

सं. का आ 266(अ)/18कक/आई डी आर ए /87, तारीख 30 मार्च, 1987,

सं. का आ 326(अ)/18कक/आई डी आर ए /88, तारीख 30 मार्च 1987

स का आ 247(अ)/18कक/आई डी आर ए /89, तारीख 31 मार्च, 1989

स का आ 277(अ)/18कक/आई डी आर ए /90, तारीख 30 मार्च, 1990 और

स का आ 214(अ)/18कक/आई डी आर ए /91, तारीख 26 मार्च 1991,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि में प्रभावी बना रहे

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (195 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक क साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का स 2/23/80 - श्री यू. एस.]

एन आर कृष्णन, अपर सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## ORDER

New Delhi, the 30th March, 1992

S.O. 250(E)|18AA|IDRA|92 :—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries Development & Regulation Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1992 [Vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)].

Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982,  
S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982,  
S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st March, 1983,  
S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983,  
S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,  
S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,  
S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985,  
S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,  
S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,  
S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,  
S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,

S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990, and  
S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1993 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2), of Section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Orders shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1993.

[F. NO. 2(23)|80-CUS]

N. R. KRISHNAN, Addl. Secy.